

राज्य सहयोग पहल के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	परियोजना
1.	सुशासन केंद्र (सीजीजी), हैदराबाद में आरटीआई कॉल सेंटर की स्थापना आंध्रप्रदेश
2.	आंध्रप्रदेश के चयनित जिलों में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ) के अंतर्गत सार्वजनिक योजनाओं से जुड़ी सूचनाओं तक नागरिकों की पहुंच बढ़ाना ।
3.	केंद्रीकृत ऑनलाइन बस पास निर्गम एवं नवीनीकरण - सुशासन केंद्र, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
4.	अत्याधुनिक स्तर पर सेवा प्रदायगी में क्षमता निर्माण - असम
5.	प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि के लिए बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बीआईपीएआरडी) को सहयोग - बिहार
6.	सेवा में सुधार पर प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ - हिमाचल प्रदेश
7.	सिविल सचिवालय, जम्मू/श्रीनगर में आगंतुक प्रबंधन प्रणाली - जम्मू एवं कश्मीर
8.	ई-एसएपी के माध्यम से बागवानी विभाग के विस्तार अधिकारियों के साथ कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की नेटवर्किंग - कर्नाटक
9.	तीन विभागों (नियामक, कल्याण एवं विकास) में लोक सेवाओं का नागरिक संतुष्टि सर्वेक्षण - केरल
10.	केरल में ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्व शासन संस्थान में प्रभावी सेवा प्रदायगी के लिए अनुकूल वातावरण को सक्षम बनाने वाले कारकों की पहचान करने संबंधी अध्ययन - केरल
11.	चयनित विभागों में संचालन के अत्याधुनिक स्तर पर कार्मिकों के लिए योग्यता ढांचा विकसित करना- केरल
12.	राज्य सेवा आयोग के आवेदन पर विशेष ध्यान देने के साथ राज्य के लिए प्रमाण-पत्र और दस्तावेज संग्रह प्रणाली के लिए सेवा उन्मुख संरचना- मणिपुर
13.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन की निगरानी - पुडुचेरी
14.	ब्लड बैंक प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली - पंजाब
15.	सरकारी और सरकार द्वारा अनुमोदित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआईज एवं

	आईटीसीज) में ऑनलाइन एडमिशन/काउंसलिंग - पंजाब
16.	नागरिक पंजीकरण प्रणाली एवं सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 का कार्यान्वयन - पंजाब
17.	एटीआई में दो राष्ट्रीय स्तर की केस स्टडी कार्यशालाएं - पश्चिम बंगाल
18.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सेवा का सुदृढीकरण- पश्चिम बंगाल
19.	पश्चिम बंगाल राज्य में सेवोत्तम के लिए क्षमता निर्माण की कार्यनीतिक योजना - पश्चिम बंगाल
20.	ई-असेंबली - जम्मू एवं कश्मीर
21.	जम्मू विकास प्राधिकरण का स्वचालन - जम्मू एवं कश्मीर
22.	असंगठित अपशिष्ट कामगारों के सुदृढीकरण के लिए आजीविका कार्यक्रम - कर्नाटक
23.	समुदाय के लिए क्षमता निर्माण - अत्याधुनिक स्तर पर लोक सेवाओं की प्रभावी प्रदायगी के लिए सरकार - ओडिशा
24.	मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन - ओडिशा
25.	उपस्थिति की निगरानी के लिए बायोमेट्रिक आधारित टैबलेट डिवाइस उपलब्ध कराना - पुडुचेरी
26.	सरकारी और सरकार द्वारा अनुमोदित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण स्थान (आईटीआईज एवं आईटीसीज) का वेबसाइट सूचना पोर्टल - पंजाब
27.	एंड टु डंड इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदायगी का समापन - पंजाब
28.	सेवाओं की प्रदायगी की निगरानी के लिए वेब एप्लिकेशन - पंजाब
29.	दिव्यांगों के लिए प्राथमिक विद्यालयों में अधिगम में अभिवृद्धि - कर्नाटक
30.	पंचायत में संचालन के अत्याधुनिक स्तर पर कार्मिकों के लिए योग्यता ढांचा विकसित करना - केरल
31.	ऑनलाइन ड्रग सूचना और निगरानी प्रणाली - पंजाब

32.	डिजिटल तेलंगाना - टीएस क्लासेज - तेलंगाना
33.	डिजिटल तेलंगाना : ई-स्वास्थ्य, तेलंगाना
34.	आपदा प्रबंधन नियंत्रण पोर्टल तेलंगाना
35.	स्थानीय हस्तशिल्प को प्रोत्साहन - अंडमान एवं निकोबार
36.	जिला - एटा में कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विभागों की विविध स्कीमों की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय परियोजना प्रस्ताव/अनुमान उत्तर प्रदेश
37.	मिजोरम लोक सेवा का अधिकार अधिनियम, 2015, मिजोरम सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सुशासन प्रकोष्ठ) के अंतर्गत सेवा प्रदायगी का सुदृढीकरण - मिजोरम
38.	ई-वेस्ट प्रबंधन पर पुनर्विचार-संधारणीय तेलंगाना के लिए विजन - आईटीई एवं सी विभाग, तेलंगाना सरकार
39.	सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास विभाग, केरल सरकार के तहत संस्थाओं के लिए नागरिक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना - सरकारी प्रबंधन संस्थान (आईएमपी) तिरुअनंतपुरम, केरल सरकार
40.	उन न्यायालय मामलों की स्थिति की निगरानी के लिए ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन का विकास जहां जिला कलेक्टर एक पक्षकार है, जिला कलेक्टर, परबानी, महाराष्ट्र सरकार
41.	रिमोट सेंसिंग तकनीक के माध्यम से अनाधिकृत निर्माण की पहचान और निर्माण और विकास गतिविधियों की निगरानी के लिए चेंज डिटेक्शन टाउन एवं कंट्री प्लानिंग विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़
42.	केंद्रीकृत प्रवेश समिति (सीईएनटीएसी), उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, पुडुचेरी सरकार + सभी सरकारी कॉलेजों की निगरानी के लिए कॉलेज प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, पुडुचेरी
43.	ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की इंवेटरी प्रबंधन प्रणाली का विकास, जम्मू एवं कश्मीर सरकार
44.	राजधानी शहर प्रशासन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ और नागरिक कॉल सेंटर, जिला प्रशासन, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर सरकार

45.	परियोजना "चांब्याल" स्थानीय कारीगरों/हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने के लिए चंबा उत्पादों को प्रोत्साहन देना ।
46.	पुलिस कर्मों मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) और प्रशिक्षण के लिए तकनीकी आधारित पुलिसकर्मों एप्लीकेशन, एसएसपी कार्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश
47.	कॉमन वेब पोर्टल और सॉफ्ट सिस्टम के साथ बुलंदशहर सिरामिक इंडस्ट्री ईको सिस्टम का विकास, जिला प्रशासन, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश सरकार ।
48.	लेबर कमिश्नरी में प्रयोक्ताओं को हो रही समस्या के समाधान के लिए ऑनलाइन सपोर्ट डेस्क का निर्माण, डिश एंड डायरेक्टरेट ऑफ वॉयलर्स, श्रम आयुक्त कार्यालय, मुंबई, महाराष्ट्र सरकार
49.	जम्मू एवं कश्मीर सरकार के रिकार्डों का डिजिटाइजेशन, जम्मू एवं कश्मीर, आईटी विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार ।
50.	जेकेआईग्राम्स (जम्मू एवं कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) - जम्मू एवं कश्मीर
51.	हिमाचल प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए डोनर-डोनी ब्रिज ई-सेवा- हिमाचल प्रदेश
52.	जिला स्मार्ट नियंत्रण कक्ष, उत्तर काशी, उत्तराखंड
53.	तमिलनाडु स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (टीएनएसडब्ल्यूएएन) की सहायता से एसपीईसीएस (सीड प्रोडक्शन इन्फोर्समेंट सर्टिफिकेशन सिस्टम) सॉफ्टवेयर कार्यक्रम का सुदृढीकरण - तमिलनाडु
54.	ई-ऑफिस परियोजना, मेघालय ।
55.	सिक्किम सरकार के लिए ई-ऑफिस, सिक्किम ।